FOR, U.G. PART-3
PAPER-VI

PARTITION OF INDIA
[PART-1]

भारत का विभाजन (भाग-1)

15 Aug. 1947 को भारत की आजादी और विभाजन की द्वैध वास्तविकता से उभरे प्रश्न इतिहासकारों सहित समूचे चेतन समाज के लिये आज भी परेशानी का सबब बने हुये हैं। आजादी तो एक लम्बे गौरवपूर्ण संघर्ष एवं बलिदान का परिणाम थी, विभाजन क्यों? क्या यह अपरिहार्य था? क्या विभाजन ही भारत की साम्प्रदायिक समस्या का वास्तविक समाधान था? राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिये दशकों तक लड़ते रहने के बाद कांग्रेस 1947 में सुस्त क्यों पड़ गयी तथा विभाजन को क्यों स्वीकार कर लिया? विभाजन कांग्रेस की हार थी या मुस्लिम लीग की जीत या फिर आजादी देने का साम्राज्यवादी तरीका? ये सभी प्रश्न उतने ही नये, कठिन एवं अनुत्तरित हैं, जितने की उस समय।

1947 में भारत की आजादी के साथ विभाजन उस राजनीतिक नाटक की परिणति था जिसकी शुरुआत हम 1930 के दशक से मान सकते हैं। वैसे इस नाटक की सामग्रियाँ 19वीं सदी के द्वितीयार्द्ध से ही तैयार हो रही थी जब विलियम हंटर की INDIAN MUSALMANS (1870) के प्रकाशित होने के बाद से ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीयता की धार को कुंद करने के लिये साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देना शुरू किया था। सर सैय्यद अहमद खाँ की संविधान की लोकतांत्रिक अवस्था में मुस्लिम हितों के खतरे की चिंता ने भी साम्प्रदायिक विचारधारा को पनपाया। 1909 के सुधारों में साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचक मंडल बनाकर इस विचारधारा को औपचारिक मान्यता दे दी गई। मुस्लिम लीग अपने आरम्भिक

Scanned with CamScanner

दौर में मुसलमानों के लिये विधान सभाओं एवं सरकारी सेवाओं में स्थान आरक्षित करने की राजनीति करती थी और जब 1916 में कांग्रेस ने उनकी उक्त मांग को मान लिया तो खिलाफत के प्रश्न पर शुरू हुये असहयोग आंदोलन में हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों ने संयुक्त रूप से साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष में भागीदारी की। परन्तु यह एकता क्षणिक सिद्ध हुई। साइमन कमीशन के विरोध में मुस्लिम लीग ने दिलचस्पी नहीं ली और 1928 में जब संवैधानिक समस्या के समाधान के रूप में "नेहरू-रिपोर्ट" तैयार हुआ तो जिन्ना के नेतृत्व में मुसलमानों का एक की मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी आरक्षण की मांग पर अड़ गया तथा जिन्नाह ने अपनी 'चौदह सूत्री' योजना रख दी।

1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष मो० इकबाल ने 'सर्व इस्लाम' की भावना से प्रेरित होकर "कम से कम उत्तर-पश्चिम भारत में" एक मुस्लिम राज्य के गठन को मुस्लिम लीग का 'अंतिम लक्ष्य' घोषित किया जिसका शेष भारत से ढीला संघ होता तथा जिसमें उ.प. सीमाप्रांत, पंजाब सिंध तथा बलूचिस्तान होते। ठीक इसके तीन वर्षों के बाद कैम्ब्रिज के कानून के एक पंजाबी छात्र ने 'अभी नहीं तो कभी नहीं' (NOW OR NEVER) नामक एक पेम्पलेट में एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की परिकल्पना की। यह 'पवित्रों की भूमि (The Land of Pure) पाकिस्तान' होता जिसमें पंजाब पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत, सिंध, बलूचिस्तान तथा काश्मिर होते। इकबाल की योजना की तरह इसे भी कोई विशेष समर्थन नहीं मिला तथा इसे एक विद्यार्थी

की योजना तथा काल्पनिक एवं अव्यावहारिक कहा गया लेकिन यही योजना बाद में पाकिस्तान आंदोलन का आधार बनी। 1935 के संवैधानिक सुधारों में यह बात साम्राज्यवादियों के दिमाग में कहीं न कहीं थी।

जिन्ना 1930 में लंदन चले गये थे लेकिन 1935 के सुधारों के तहत हो रहे चुनावों के लिये मुस्लिम लीग को पुनर्संगठित करने के उद्देश्य से 1935 के अंत में पुन: भारत लौट आये। वे इस समय तक भारतीय एकता की बात करते थे और उनका मकसद चुनावों में मुस्लिम लीग के माध्यम से ज्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस को एक और समझौते के लिये बाध्य कर देना था तथा इसीलिए कहीं कहीं चुनाव प्रचार के लिये उन्होंने धर्म का सहारा भी लिया। लेकिन 1937 के चुनाव परिणाम मुस्लिम लीग तथा जिन्ना के लिये निराशाजनक थे। पृथक मतदाता मंडलों की व्यवस्था के तहत मुसलमानों को आवंटित 482 सीटों में से 109 पर ही लीग विजयी हो सकी तथा उसे कुल मुस्लिम वोटों का मात्र 4.8% ही मिला। जबकि कांग्रेस को 58 मुस्लिम सीटों पर 26 में विजय मिली।

1937 का वर्ष विभाजन की कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। संयुक्त प्रांत में खलीकुज्जमा ने कांग्रेस से लीग के साथ मिलकर सरकार बनाने का आग्रह किया परंतु संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत था और उसने ऐसा करने से इंकार कर दिया। ऐसा कर वह सभी भारतीयों का प्रतिनिधि होने के अधिकार को खोना नहीं चाहती थी। लीग चाहती थी कि उसे मुस्लिमों का एकमात्र पार्टी मान ली जाये पर यह कांग्रेस के राष्ट्रीय चरित्र के खिलाफ था। इस घटना के कारण और बाद के दो वर्षों में

Scanned with CamScanner

कांग्रेसी सरकारों के कार्यों से मुस्लिमों में अलगाववाद की भावना पनपी।

जिन्ना के लिये यह राजनीतिक परीक्षा की घड़ी थी। राजनीति में बने रहने के लिये उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ साम्प्रदायिक दुष्प्रचार किया। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार से मिलकर भारत में हिन्दू राज्य कायम करना चाहती है तथा भारत से इस्लाम का नामोनिशां मिटा देना चाहती है। मौलाना आजाद जैसे राष्ट्रवादी मुसलमानों को 'इस्लाम के गद्दार' कांग्रेस के नुमाइशी बच्चे तथा हिन्दुओं के भाड़े के टट्टू' करार दिया गया। जिन्ना इस प्रचार से लोकप्रिय होने लगे। 23 March 1940 को लाहौर के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जिन्ना ने 'द्विराष्ट्र सिद्धांत' को मान्यता दे दी एवं स्वतंत्र एवं पृथक पाकिस्तान की प्राप्ति को मुस्लिम लीग का लक्ष्य घोषित किया।

साम्राज्यवादियों को इसमें कुछ भी बुरा न लगा। 8 Aug. 1940 को वायसराय लार्ड लिनलिथगो ने 'अगस्त-प्रस्ताव' में अल्पसंख्यकों को विश्वास दिलाया कि भावी संविधान उनकी अनुमति से ही बनेगा। क्रिप्स प्रस्ताव (1942) ने पहली बार पाकिस्तान की संभावना को सार्वजनिक स्वीकृति दी जिसमें भावी संविधान में प्रांतों को ऐच्छिक रूप से शामिल होने की बात कही गई थी। प्रांतों को भारत संघ में सम्मिलित होने या न होने का अधिकार देकर वास्तव में मुस्लिम लीग को पाकिस्तान निर्माण का अप्रत्यक्ष प्रलोभन दिया गया।

[क्रमशः जारी]

Scanned with CamScanner